भूमिहीनों को अधिशेष भूमि का आवंटन

1322. **डा० रत्नाकर पाण्डे** : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों से पांच से छः लाख हैक्टेयर अधिशेष भूमि पहली सितम्बर, 1992 तक भूमिहीनों को बांटने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां तो इस पर राज्य सरकारों की प्रतिक्रिया क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) और (ख) 14 मार्च, 1992 को हुए राज्यों के राजस्व मंत्रियों के सम्मेलन में लिए गए निर्णयों में से एक निर्णय यह लिया गया था कि विवाद मुक्त अधिकतम सीमा से फालतू भूमि के वितरण का कार्य 30 जून, 1992 तक पूरा कर लिया जाए और राजस्व न्यायालयों में मुकदमेंबाजी में फंसी 75 प्रतिशत भूमि को ऐसी मुकदमेबाजी से मुक्त कर इसे वितरण के लिए उपलब्ध कराया जाए तथा इसके वितरण का कार्य 30 सितम्बर, 1992 तक पूरा कर लिया जाए ।

इस सम्मेलन की सिफारिशों को राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को उपयुक्त कार्यवाई करने के लिए भेज दिया गया है ।

मध्यप्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य

@1323. **श्री अजीत जोगी : कुमारी अलिया :**

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991-92 के दौरान मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत क्या-क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये थे और उनमें से अब तक कितने लक्ष्य प्राप्त कर लिये गये हैं ; और

(ख) यदि सम्पूर्ण लक्ष्य की प्राप्ति में कोई कमी हो, तो उसे दूर करने के लिए सरकार ने क्या-क्या सुधारात्मक कदम उठाये हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) और (ख) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (एन. आर. ई. पी.) को 1-4-1989 से समाप्त कर दिया गया है । तथापि जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के लिए वर्ष 1991-92 हेतु निर्धारित किए गए 966.90 लाख श्रम दिनों के रोजगार सृजन के लक्ष्य के मुकाबले फरवरी, 1992 के अन्त तक 779.01 लाख श्रमदिनों का रोजगार सृजित किये जाने की सूचना मिली है, जो वार्षिक लक्ष्य के 80 प्रतिशत से अधिक है । अतः मध्य प्रदेश में योजना के अन्तर्गत उपलब्धि संतोषजक मानी गई है ।

ग्रामीण विकास के लिए आवंटन

1324. **श्री रणजीत सिंह :**

श्रीमती सुषमा स्वराज :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 31 मार्च 1992 के "इकोनामिक टाइम्स" में "रूरल डेवलपमेंन्ट एलोकेशन कट टू बी रेस्टोर्ड" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि गत वर्ष ग्रामीण विकास शीर्ष के अंतर्गत बजट प्रावधानों में की गई 500 करोड़ रुपये की कटौती को बहाल करने का निश्चय किया गया है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि गत वर्ष बजट प्रावधानों में की गई इस कटौती के कारण ग्रामीण विकास की अनेक योजनाओं को बंद करना पड़ा था ;

(घ) यदि हां, तो इस कटौती के कारण कितने ग्रामीण लोगों के प्रभावित होने की अनुमान है; और

@पूर्वतः अतारांकित प्रश्न 588, 4 मई, 1992 से स्थानान्तरित ।